

3 राजधानी
केजीएमयू ने 2022 संकाय
भर्ती की सूची जारी की

6 अभिमत
जल संकट से निपटने
के उपाय

11 विदेश
भारतीय रक्षा उद्योग को अफ्रीका
में साझेदारी की उम्मीद

12 स्पोर्ट्स
अश्विन ने बांग्लादेश के
विरुद्ध ठोंका शतक



लखनऊ, नई दिल्ली और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com



स्वच्छता से ही भारत
स्वस्थ और विकसित
बनेगा: राष्ट्रपति
राष्ट्रीय-9

भारत नहीं पाक में है कांग्रेस, नेकां की पूछ: पीएम



जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान रिवासी जिले के कटरा में रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
जम्मू-कश्मीर विस चुनाव
मोहित कंधारी। कटरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस-नेशनल कॉंग्रेस पर निशाना साधाते हुए कहा पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए उनके घोषणापत्र पर बल्ले-बल्ले कर रहा है। माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर कटरा टाउनशिप में रोड शो करने के बाद एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस-नेशनल कॉंग्रेस को लेकर जम्मू-कश्मीर में भले ही उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। पीएम ने गठबंधन के सहयोगियों पर पाकिस्तान के हितों के साथ तालमेल करने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खजाजा आसिफ के एक साक्षात्कार के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 की बहाली पर पाकिस्तान और एनसी-कांग्रेस गठबंधन एकमत हैं।

कटरा की रैली में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस-नेशनल कॉंग्रेस (कांग्रेस) को बहाली पर पाकिस्तान और एनसी-कांग्रेस गठबंधन एकमत हैं। पाकिस्तान को बहाली पर पाकिस्तान और एनसी-कांग्रेस गठबंधन एकमत हैं। पाकिस्तान को बहाली पर पाकिस्तान और एनसी-कांग्रेस गठबंधन एकमत हैं। पाकिस्तान को बहाली पर पाकिस्तान और एनसी-कांग्रेस गठबंधन एकमत हैं।

स्टैंडियम में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण में भारी मतदान की सराहना करते हुए कहा कि यह उन पार्टियों को अस्वीकृत को दर्शाता है जो पश्चरवाजों और आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखते हैं। तीनों परिवार कश्मीरियों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं, और यह शुरू से ही उनका एजेंडा है। तीनों परिवार सोचते हैं कि उनसे सवाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन, जम्मू-कश्मीर इन परिवारों के कब्जे में नहीं रहेगा। पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर तीखा हमला जारी रखते हुए कहा, उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों को केवल हिंसा दी है। जम्मू-कश्मीर के युवा अब वंशवादी राजनीति को चुनौती दे रहे हैं। यह वही युवा हैं जिन्हें इन पार्टियों ने आगे बढ़ने नहीं दिया। तीनों परिवार जम्मू-कश्मीर की राजनीति को अपनी पारिवारिक संपत्ति मानते थे। उन्होंने किसी और को मंच पर नहीं आने दिया। यही कारण है कि इन परिवारों ने पंचायत चुनाव होने से रोक दिया क्योंकि उन्हें लगा कि नए लोग आ जाएंगे और उनकी जगह ले लेंगे। इसके परिणामस्वरूप युवाओं का लोकतंत्र में भरोसा खत्म हो गया। उन्हें लगा कि वे वोट दें या न दें, सत्ता इन तीन परिवारों के पास ही रहेगी। पीएम ने अपने खस अंदाज में एशकों से अतीत के बारे में सवाल करते हुए कहा, क्या आपको याद है कि पहले चुनाव कैसे होते थे। (शेष पृष्ठ 9)



लेबनान के बेरुत में लेबनानी सेना के बग निरोधक विशेषज्ञ अमेरिकन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की पार्किंग में मिले वांकी-टॉकी को निष्क्रिय करने का प्रयास करते हुए।
एपी/पीटीआई

हिजबुल्लाह ने दागे उत्तरी इजराइल में कई रॉकेट

एजेंसी। बेरुत
हिजबुल्लाह ने गुस्वार को उत्तरी इजराइल में नया हमला किया। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के उत्तरी इलाकों को निशाना बनाता रहा है। क्योंकि लेबनान में सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विस्फोट होने के बाद बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है, जिसमें कम से कम 32 लोग मारे गए और 3,000 से अधिक अन्य घायल हो गए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विस्फोट इजरायल द्वारा एक साथ अधिक से अधिक हिजबुल्लाह सदस्यों को निशाना बनाने के लिए महीनों तक चले अभियान का परिणाम प्रतीत होता है। पिछले दो दिनों में, हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए गए पेजर और वांकी-टॉकी को निष्क्रिय हो गए, जिससे कुछ लड़ाकू घायल हो गए और यहां तक कि अपंग भी हो गए, लेकिन समूह की सामाजिक शाखाओं से जुड़े नागरिक भी अपंग हो गए और कम से कम दो बच्चे मारे गए। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह हमला हाल के हफ्तों में इजरायली नेताओं द्वारा दी गई चेतावनियों से कैसे मेल खाता इजरायल सरकार ने इसे ईरानी समर्थित समूह की सीमा पार से गोलीबारी को समाप्त करने के लिए युद्ध का लक्ष्य बताया है ताकि हजारों इजरायली सीमा के पास अपने घरों में वापस लौट सकें। बुधवार को इजरायली सैनिकों से बात करते हुए, इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा, (शेष पृष्ठ 9)

पन्नु केस में अमेरिकी अदालत के समन पर भारत ने जताया सख्त एतराज

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में दायर एक सिविल मुकदमे में अमेरिकी अदालत द्वारा भारत सरकार को भेजे गए समन पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बुधवार को इसे अनुचित और निराधार आरोप करार दिया। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय ने समन में भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल (एनएसए) और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल का नाम लिया है। विदेश सचिव मिसरी ने कहा, 'जैसा कि हमने पहले भी कहा है, वे पूरी तरह से अनुचित और निराधार आरोप हैं। अब जब यह विशेष मामला दर्ज हो गया है, तो इससे अंतर्निहित स्थिति के बारे में हमारे विचार नहीं बदलेंगे। मैं केवल आपका ध्यान इस विशेष मामले के पीछे के व्यक्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसका इतिहास सर्वविदित है। उन्होंने कहा, 'मैं इस तथ्य को भी रेखांकित करना चाहूंगा कि जिस संगठन का यह व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है, वह एक गैरकानूनी संगठन है, जिसे 1967 के गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत ऐसा घोषित किया गया। यह निर्णय भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के उद्देश्य और राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के कारण लिया गया।



यूनाईटेड किंगडम (यूके) के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने नवंबर में बताया था कि अमेरिकी ने पन्नू की हत्या की साजिश को विफल कर दिया है, जिसके पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता थी।

यूनाईटेड किंगडम (यूके) के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने नवंबर में बताया था कि अमेरिकी ने पन्नू की हत्या की साजिश को विफल कर दिया है, जिसके पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता थी। उन्होंने कहा, 'मैं इस तथ्य को भी रेखांकित करना चाहूंगा कि जिस संगठन का यह व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है, वह एक गैरकानूनी संगठन है, जिसे 1967 के गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत ऐसा घोषित किया गया। यह निर्णय भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के उद्देश्य और राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के कारण लिया गया।

आतंकवाद और धन शोधन से निपटने में भारत प्रभावी : एफएटीएफ

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

वैश्विक धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण निरोधक निकाय (एफएटीएफ) ने बुधवार को भारत पर अपनी बहुप्रतीक्षित पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि देश की प्रणालियाँ 'प्रभावी' हैं, लेकिन इन मामलों में अभियोजन को मजबूत करने के लिए 'बड़े सुधारों' की आवश्यकता है। पेरिस मुख्यालय वाली संस्था ने मूल्यांकन को अपनाए जाने के बाद जून में अपनी पूर्ण बैठक में 368 पृष्ठों की रिपोर्ट जारी की। भारत की धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण व्यवस्था की पिछली ऐसी समीक्षा 2010 में प्रकाशित हुई थी।



एफएटीएफक विशेषज्ञों के भारत के दौर के बाद आई इस रिपोर्ट ने देश को 'लगातार नजर बनाए रखने' वाली श्रेणी में रखा है, यह एक ऐसा अंतर है जिसे केवल चार अन्य जी20 देश ही साझा करते हैं।

भारत की एएमएल/सीएफटी प्रणाली की प्रभावशीलता के स्तर का विश्लेषण करती है, और इस बारे में सिफारिशें प्रदान करती है कि कैसे प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (राजस्व) विवेक अग्रवाल ने कहा कि वैश्विक अपराध निगरानी संस्था एफएटीएफ ने वित्तीय खुफिया जानकारी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के जोखिमों के साथ-साथ लाभकारी स्वामित्व के प्रकटीकरण सहित मापदंडों पर भारत को उच्च रेटिंग दी है। एफएटीएफ द्वारा की गई सिफारिशों में से, आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में तेजी से सुनवाई महत्वपूर्ण है। अग्रवाल ने कहा कि बाकी सिफारिशों सहयोग प्रकृति की हैं। अग्रवाल ने कहा, हमने इस परीक्षा को बखूबी पास कर लिया है।

पिछले नवंबर में एफएटीएफक विशेषज्ञों के भारत के दौर के बाद आई इस रिपोर्ट ने देश को 'लगातार नजर बनाए रखने' वाली श्रेणी में रखा है, यह एक ऐसा अंतर है जिसे केवल चार अन्य जी20 देश ही साझा करते हैं। भारत का अगला मूल्यांकन 2031 में होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने ऐसी धन शोधन निरोधक (एएमएल) और आतंकवाद वित्तपोषण निरोधक (सीएफटी) प्रणाली लागू की है जो कई मामलों में प्रभावी थी। हालांकि, इसमें कहा गया

उन्होंने कहा कि चूंकि भारत एफएटीएफ के अनुसार नियमित रूप से लगातार कार्रवाई कर रहा है, इसलिए देश तीन साल बाद जोखिम अंकावकनी की रिपोर्ट कर सकता है। अग्रवाल ने कहा, लेकिन हम पर कोई बाधकता नहीं है। गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) द्वारा आतंकवाद के वित्तपोषण के दुरुपयोग को संभावना पर (शेष पृष्ठ 9)

रामपुर में रेल पट्टी पर मिला टेलीफोन तार लगाने वाला खंभा, हादसा होते-होते बचा

भाषा। रामपुर, नई दिल्ली

प्रदेश के रामपुर में बलवंत एन्वेलो कॉलोनी के पास अराजक तत्वों ने रेल की पट्टी पर टेलीफोन तार लगाने में इस्तेमाल होने वाला एक पुराना खंभा रख दिया हालांकि ट्रेन चालक के आपातकालीन ब्रेक लगाते से हादसा टल गया। रेलवे सूत्रों ने यह जानकारी दी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि घटना बुधवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर में सुधार की आवश्यकता है। सिटी रेलवे स्टेशन के पास हुई। रेल मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने ट्रेन पलटने को कोशिश की आशंका जताते हुए कहा, 18 सितंबर को रात 10 बजेकर 18 मिनट पर ट्रेन संख्या 12091 के लोको पायलट ने रद्दपुर सिटी के स्टेशन मास्टर को सूचना दी कि चूंकि भारत एफएटीएफ के अनुसार नियमित रूप से लगातार कार्रवाई कर रहा है, इसलिए देश तीन साल बाद जोखिम अंकावकनी की रिपोर्ट कर सकता है। अग्रवाल ने कहा, लेकिन हम पर कोई बाधकता नहीं है। गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) द्वारा आतंकवाद के वित्तपोषण के दुरुपयोग को संभावना पर (शेष पृष्ठ 9)

बिहार में 21 दलितों के घर फूँके

पायनियर समाचार सेवा। पटना

बिहार के नवादा जिले में दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी। शुरुआती जांच में पता चला है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मांझी टोला में बुधवार देर शाम हुई इस घटना के पीछे भूमि विवाद हो सकता है। नवादा के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा ने बताया कि जिला पुलिस ने घटना के सिलसिले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य लोगों की तलाश जारी है। मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।



बिहार के नवादा जिले में कई घरों में आग लगाए जाने के बाद के बचे अवशेष। पीटीआई

आशुतोष कुमार वर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मांझी टोला में एक समूह ने करीब 21 घरों को जला दिया, जिनमें से कुछ आधे-पक्के थे। मौके पर मौजूद वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी क्षतिग्रस्त घरों की सही संख्या की जानकारी देते हुए रिपोर्ट देंगे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि घरों में आग लगाने के दौरान हवा में गोलियाँ भी चलाई गईं। जांच से पता चला है कि कुल 34 घरों में से 21 पूरी तरह से जल गए और 13 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। संदिग्धों को पकड़ने के लिए तलाशी जारी है।

उन्होंने कहा, विस्थापित लोगों को भोजन के खाने के पैकेट और पीने के पानी सहित अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। पीड़ितों के अस्थायी टेंट लगाए गए हैं। डीएम ने मवेशियों को जलाए जाने के दावों का खंडन करते हुए कहा, इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा जिले में 34 घरों को आग लगाने की निंदा की, जिनमें से ज्यादातर एससी/एसटी समुदायों के थे और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून) और व्यवस्था) को घटनास्थल का दौरा करने और जांच की निगरानी करने को कहा। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में डबल इंजन सरकार है और दलितों के

भारत के जीवंत और खूबसूरत आदिवासी क्षेत्रों से लोगों को रूबरू कराने की तैयारी

अर्चना ज्योति। नई दिल्ली

भारत के आदिवासी क्षेत्रों की अतुल्य सुंदरता और जीवंत संस्कृति को और करीब से देखने और साक्षात्कार करने का शानदार मौका मिलने जा रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इस दिशा में आदिवासी समुदायों को अपने घरों में पर्यटकों का स्वागत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट योजनाएं चला रही है इससे उनके अपनी अनूठी विरासत को बाहर के लोगों से साझा करने का मौका मिलेगा। इस उल्लेखनीय पहल का समर्थन करते हुए, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों के आदिवासी इलाकों में पर्यटन की

संभावना वाले गांवों में 1,000 होमस्टे को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस योजना उद्देश्य आदिवासी समुदायों को समृद्ध परंपराओं को संरक्षित करने के साथ-साथ उनकी आय में बढ़ोतरी करना है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उनके सतत विकास को बढ़ावा मिल सके। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय अपने स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक पर्यटन की संभावना वाले आदिवासी गाँव में 5 से 10 होमस्टे के निर्माण के लिए आदिवासी परिवारों और गाँवों को धन मुहैया कराने की योजना बना रहा है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस संबंध में विवरण साझा करते हुए कहा, प्रत्येक परिवार दो नए कमरों के निर्माण के लिए 5 लाख रुपये और

मौजूदा कमरों के नवीनीकरण के लिए 3 लाख रुपये तक और गांव समुदाय की आवश्यकता के लिए 5 लाख रुपये के पात्र होंगे। पात्र होगा। उन्होंने कहा कि योजना प्रारंभिक चरण में है और यह सुनिश्चित करने के लिए वारिकियों पर काम किया जा रहा है ताकि नियमों का उल्लंघन न हो और आदिवासियों और आगतुकों के अधिकारों की रक्षा हो। आदिवासी क्षेत्रों में मंत्रालय की होमस्टे योजना केंद्र की प्रमुख प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का हिस्सा है, जिसे एक दिन पहले केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय ने मंजूरी दी थी। योजना के लिए कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा : 56,333 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा



: 22,823 करोड़ रुपये) के साथ, इस योजना का उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतुष्टि

कवरेज को अपनाकर आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इस योजना से 63,000 गांवों में लगभग 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ मिलने की उम्मीद है क्योंकि 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी आदिवासी बहुल गांवों में फैले 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों को कवर किया जाएगा। मिशन में 25 हस्तक्षेप/योजनाएं शामिल हैं जिन्हें 17-लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। अधिकारी के अनुसार, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अगले 5 वर्षों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत उन्हें आवंटित धन के माध्यम से समर्थन

तरीके से इससे संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 10.45 करोड़ है और देश भर में 705 से अधिक आदिवासी समुदाय दूरदराज और पहुंच से दूर के इलाकों में रहते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने आदिवासी क्षेत्रों में होमस्टे की योजना को आगे बढ़ाया है, वहीं मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड (एमपीटीबी) पहले से ही इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। एमपीटीबी की होमस्टे परियोजना के तहत कई आदिवासी परिवारों ने अपने घरों को होमस्टे के रूप में खोला है और अब वे आगतुकों की मेजबानी के लिए तैयार हैं। एमपीटीबी अधिकारियों के अनुसार, ग्रामीण आदिवासी समुदायों ने 28 गांवों में 64 से अधिक नए होमस्टे स्थापित किए हैं। कोविड के बाद, होमस्टे अद्वितीय और व्यक्तिगत अनुभव चाहने वाले यात्रियों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन गए हैं। वे अक्सर मेहमानों को स्थानीय संस्कृति में डूबने, घर के बने भोजन का आनंद लेने और अनदेखे आकर्षणों तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। घर के मालिकों के लिए, किसी संपत्ति को होमस्टे में बदलना आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है, जिससे उन्हें एक स्थिर आय प्राप्त होती है और साथ ही उन्हें अपना स्थान और आदिवासी दुसूरों के साथ साझा करने की अनुमति मिलती है। (शेष पृष्ठ 9)

उन्नाव में खुलेगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का नया परिसर

● उच्च शिक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सौंपा प्राधिकार पत्र

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उन्नाव में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का नया परिसर खुलेगा। यह परिसर उन्नाव जिले के ग्राम पदसंदन, परगना गोरिन्दा परसंदन, तहसील हसनगंज में 63.53 एकड़ भूमि पर निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। गुरुवार को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सचिवालय में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी (सीयू) इंटरनेशनल एजुकेशनल ट्रस्ट, चंडीगढ़ के प्रतिनिधियों को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्राधिकार पत्र सौंपा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को उन्नाव में स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा बाई



सर्वलेशन मंजूरी प्रदान की गई थी। योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का लाभ मिलेगा। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का यह नया परिसर लखनऊ-कानपुर हाईवे के किनारे स्थापित होगा, जो उन्नाव और आसपास के जिलों के छात्रों के लिए

एक सुनहरा अवसर साबित होगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का यह निर्णय प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगा। इससे न केवल प्रदेश के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी, बल्कि

इससे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विस्तार के लिए प्रयासरत है।

चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की उन्नाव में स्थापना प्रदेश के शिक्षा जगत में एक नया अध्याय साबित होगी। इससे प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता में वृद्धि होगी, जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और भविष्य के बेहतर अवसर लेकर आएगी। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, उन्नाव की स्थापना से छात्रों को अत्याधुनिक शिक्षा प्रणाली का लाभ मिलेगा। यह विश्वविद्यालय छात्रों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय प्रदेश के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा और उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।

जारी की गई अधिसूचना

विशेष सचिव गिरिजेश कुमार ल्यागी द्वारा 19 सितंबर, 2024 को सीयू इंटरनेशनल एजुकेशनल ट्रस्ट के सचिव/चेयरमैन को एड्रेस करते हुए अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार, निजी क्षेत्र के अंतर्गत चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, उन्नाव का नाम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 के तहत उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची-2 में क्रमांक 45 पर सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव, उत्तर प्रदेश के संचालन को अनुमति भी प्रदान की गई है। इस अधिसूचना के तहत विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से आधिकारिक मान्यता प्राप्त हो गई है। साथ ही विश्वविद्यालय से अपेक्षा की गई है कि वह प्राधिकार पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय का संचालन करेगा।

राजमवन में मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता के प्रति लोगों को किया गया जागरूक



● सेवा पखवाड़ा के तहत राजमवन में हो रहा है विविध कार्यक्रम

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में 'स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा' के तहत गुरुवार को राजभवन में राजभवन के कार्मिकों, अध्यासित छात्र-छात्राओं तथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। राजभवन के बड़े लॉन पर राष्ट्रीय झण्डे के नीचे मानव श्रृंखला बनाकर लोगों ने अपने आसपास एवं समाज को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर 'स्वभाव

स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता' की थीम पर स्वच्छता हेतु संदेश का प्रसार किया गया। भारत माता की जय एवं वन्दे मातरम के उद्घोष द्वारा लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वच्छता हेतु संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन विशेष कार्याधिकारी शिक्षा डॉ फंकन एल जानी तथा नेतृत्व मुख्य सुरक्षा अधिकारी अजय त्रिपाठी द्वारा किया गया।

विदित है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितम्बर, 2024 से शुरू होकर गांधी जयंती 02 अक्टूबर, 2024 तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा के तहत 'स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता' थीम पर आधारित स्वच्छता ही सेवा अभियान पूरे देश में संचालित हो रहा है।

इंद्रा यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में एकओएपी का दबदबा

लखनऊ। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय का रजत जयंती वर्ष समारोह सात मई 2024 से आठ मई 2025 तक मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर विश्वविद्यालय परिसर में इंद्रा यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में गुरुवार को एकओएपी 11 ने अपने सभी मैच जीतकर दबदबा बनाया।

टीम ने क्रिकेट मैच, बॉलीबॉल, और टेबिल टेनिस के सभी मैच जीते। क्रिकेट में एकओएपी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में मोहित यादव के 20 रन की पारी से 85 रन बनाये। जवाब में वीसी 11 की पूरी टीम 33 रन पर ऑलआउट हो गयी। वहीं, बॉलीबॉल में 2-0 से डीन 11 को पराजित किया। जबकि टेबिल टेनिस के महिला सिंगल्स में केश 11 को हरा कर विजता बनी। वहीं महिला डबल्स में भी एकओएपी की टीम ने केश को मात दिया। वहीं कैरम के दो मैच हुए जिसमें केश 11 ने सीओई 11 को तो मैनेजमेंट 11 ने कुलसचिव 11 को हरा दिया।

बोर्ड परीक्षा 2025 की ऑनलाइन परीक्षा केंद्र निर्धारण की समय सारिणी जारी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

यूपी बोर्ड ने वर्ष 2025 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्र निर्धारण प्रक्रिया की आधिकारिक समय-सारिणी जारी कर दी है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि परीक्षा की शुचिता, गुणवत्ता, और नकल-विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। समय-सारिणी के अनुसार, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 25 सितंबर, 2024 से शुरू होकर 28 नवंबर, 2024 तक पूरा किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत सभी विद्यालयों को अपने संस्थान की भौतिक संसाधनों से संबंधित सूचनाएं परिषद की वेबसाइट पर 25 सितंबर, 2024 तक अपलोड करनी होंगी। इसके बाद गठित तहसील स्तरीय समिति द्वारा रिपोर्ट सेंसिंग में त्रुटिपूर्ण पाए गए विद्यालयों को अपने सही

जियोलोकेशन विवरण 30 सितंबर, 2024 तक मोबाइल एप के जरिए अपलोड करने होंगे। विद्यालयों द्वारा अपलोड की गई जानकारी का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा गठित तहसील स्तरीय समिति द्वारा 15 अक्टूबर, 2024 तक किया जाएगा। इसके बाद यह समिति जिलाधिकारी को अपनी अभ्युक्ति सहित रिपोर्ट देगी, जिसे 20 अक्टूबर, 2024 तक ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा। इसके आधार पर ऑनलाइन चयनित परीक्षा केंद्रों की सूची 2 नवंबर, 2024 तक सार्वजनिक की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक, समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापित जारी कर प्रधानाचार्य, प्रबंधक, छात्र, और अभिभावकों से आपत्तियां और शिकायतें 6 नवंबर, 2024 तक प्राप्त करेंगे। इन आपत्तियों का निस्तारण 11 नवंबर, 2024 तक किया जाएगा। परिषद द्वारा अनुमोदित परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची 15 नवंबर, 2024 तक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

सरकारी अधिकारी कल 125 टीबी मरीजों को गोद लेंगे

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की प्रेरणा से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी 125 ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) मरीजों को गोद लेंगे। शनिवार को एसजीपीजीआई में स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रम में सचिवालय और महानिदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के ये अधिकारी सभी मरीजों को निःश्वय पोर्टली वितरित करेंगे।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि सामुदायिक सहायता, जागरूकता में वृद्धि और टीबी कार्यक्रम को जनादोलन बनाने की प्राथमिकता के साथ प्रदेश को टीबी मुक्त करने के लिए सूबे की सरकार के प्रयास जारी हैं। सरकार और अन्य सहयोगी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रयासों के फलस्वरूप, टीबी मुक्त प्रदेश का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने



बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे निःश्वय मित्र संस्थानों के माध्यम से टीबी जैसे गंभीर रोग के बारे में हर स्तर पर जागरूकता फैलाने के संभव प्रयास करने होंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस रोग को हराने के लिए टीबी मरीजों की हर संभव सहायता की जाए। यदि हम सकल एक साथ मिलकर सामूहिक प्रयास करें तो टीबी मुक्त प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

केजीएमयू ने 2022 संकाय भर्ती की सूची जारी की, मिलेंगे 75 नियमित शिक्षक

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

किंग्स जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर 2022 के विज्ञापन के तहत सम्पन्न हुई संकाय भर्ती के परिणामों की घोषणा कर दी है। सूची के मुताबिक विभिन्न विभागों को 75 नियमित शिक्षक मिलेंगे। इनमें 3 प्रोफेसर, 8 एसोसिएट प्रोफेसर और 64 सहायक प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र जारी किया है।

बता दें कि यह भर्ती, जो आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में कई अभ्यवेदन के कारण समीक्षाधीन थी, अब कानूनी आदेशों के अनुपालन में पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। केजीएमयू की कुलाधिपति ने 18 सितंबर 2024 को विश्वविद्यालय प्रशासन को विज्ञापित पदों की नियुक्ति के लिए बुलाई गई चयन

समितियों की सिफारिशों को कार्यकारी परिषद के समक्ष रखने के निर्देश जारी किए। राजभवन से प्राप्त निर्देश के आधार पर कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने सूची जारी की है। नवनियुक्त संकाय सदस्य विश्वविद्यालय के विकास को काफी बढ़ावा देंगे और शिक्षण पद्धतियों को बढ़ाने और विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभागों में रोगी देखभाल सेवाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उल्लेखनीय नियुक्तियों में नेफ्रोलॉजी विभाग और न्यूकिलियर मेडिसिन विभाग में विश्वविद्यालय का प्रथम नियमित संकाय सदस्य सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त पेनेस्थिसियोलॉजी विभाग के लिए 12 नई भर्तियां से सर्जरी के लिए प्रतीक्षा समय कम हो जायेगी। सर्जिकल और आईसीयू सेवाएं भी मजबूत होंगी।

एलडीए ने गोमती नगर में चलाया अभियान 4 अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किये गये

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

गोमतीनगर में एलडीए द्वारा चार अवैध निर्माण को सीलिंग कार्रवाई की गयी। एलडीए के विहित प्राधिकारी द्वारा अवैध निर्माण नोटिस जारी कर सीलिंग आदेश दिए थे। आदेश पर प्रवर्तन टीम द्वारा सीलिंग कार्रवाई की गयी।

गुरुवार को एलडीए ने गोमती नगर क्षेत्र में कार्यवाही की। प्रवर्तन जोन.1 के जोनल अधिकारी देवाश शिवेदी ने बताया कि ओम प्रकाश गुप्ता व अन्य द्वारा गोमती नगर के विवेक खण्ड में भूखण्ड संख्या.4/299 पर लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक निर्माण कराया गया था। वहीं, कुमारिल भट्ट व अन्य द्वारा गोमती



नगर के विकास खण्ड में भूखण्ड संख्या.सी.3/46 पर लगभग 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक निर्माण कराया गया था। इसी तरह विद्या प्रसाद व अन्य द्वारा गोमती नगर के विराम खण्ड में भूखण्ड

संख्या.2/391 पर लगभग 115 वर्गमीटर क्षेत्रफल में भवन का निर्माण कराया जा रहा था। इसके अलावा आरके वर्मा व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार के सेक्टर.4 में भूखण्ड संख्या.4/964 पर लगभग 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल में भवन का निर्माण कराया गया था।

प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किये जा रहे इन निर्माण कार्यों के विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद दर्ज करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। आदेश पर सहायक अभियंता उदयवीर सिंह, अवर अभियंता विपिन बिहारी राय व सुरेन्द्र द्विवेदी द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से चारों निर्माणों को सील कर दिया गया।

एलडीए में रजिस्ट्री, फ्रीहोल्ड हो या नामांतरण जनता की मदद के लिए तैनात होंगे प्राधिकरण मित्र

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

एलडीए में सम्पत्ति आवंटन, रजिस्ट्री, फ्रीहोल्ड व नामांतरण कार्यों के लिए आने वाले लोगों को अब अलग-अलग अनुभागों के चक्र नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्हें एक ही जगह पर अपने समस्त कार्यों की जानकारी मिल जाएगी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने जन सामान्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनसंपर्क प्रणाली को सिंगल विन्डो सिस्टम के तहत एकीकृत करने का आदेश जारी किया है। इसके तहत एलडीए में प्राधिकरण मित्र तैनात किये जाएंगे, जो आम नागरिकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए उनके कार्य निस्तारित कराएंगे।

एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्राधिकरण भवन में सम्पत्ति, रजिस्ट्री, फ्रीहोल्ड, नामांतरण व बुकिंग संबंधी कार्यों के लिए आने वाले लोगों को सही जानकारी न होने के कारण अलग-अलग पटलों में भटकना पड़ता है। इससे लोगों को असुविधा होती है और विभागीय कार्य भी

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जन सामान्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनसंपर्क प्रणाली को किया एकीकृत

बाधित होता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण भवन के गेट नंबर.2 के पास निर्मित काउंटरों को अपग्रेड करते हुए जनसंपर्क के लिहाज से उपयोगी बनाया जाएगा। इसमें ई.स्टाम्प, ई.चालान, नामांतरण-फ्रीहोल्ड, सामान्य पृच्छाछ, व्यावसायिक सम्पत्ति, मानचित्र, आईजीपी/पार्कस की बुकिंग, हाईटेक/इटीग्रेटेड टाउनशिप, लोन डेस्क से सम्बंधित कार्यों के आवेदन प्राप्त किये जाएंगे। प्रत्येक काउंटर पर सम्बंधित अनुभाग के 2 कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी, जिन्हें प्राधिकरण मित्र कहा जाएगा। प्राधिकरण मित्र द्वारा आम जनता को सम्बंधित कार्य की पूरी जानकारी देने के साथ ही सत्यबद्ध तरीके से उनका कार्य निस्तारित कराया

गोवंश आश्रय केन्द्र में बड़इंतजामी देखकर मड़के एसडीएम, लगाई फटकार



संवाददाता। मोहनलालगंज

निराश्रित गोवंश आश्रय केन्द्र खुशीली का औचक निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम ब्रजेश कुमार वर्मा को बड़इंतजामी की भरमार मिली। स्टॉक रजिस्टर समेत अन्य अभिलेख मौजूद न मिलने पर एसडीएम ने मातहतों को कड़ी फटकार लगाई। बीमार गोवंश के लिए सिक वार्ड न होने और गोवंश की देखरेख ठीक ढंग से न किए जाने को लेकर भी एसडीएम ने गहरी नाराजगी जताई। एसडीएम ने बीडीओ और डिप्टी सीबीओ से चारे के भुगतान और अभिलेखों का सत्यापन कर रिपोर्ट मांगी है।

मोहनलालगंज के निराश्रित गोवंश आश्रय केन्द्र खुशीली का

गुरुवार को जायजा लेने पहुंचे एसडीएम ब्रजेश कुमार वर्मा को चरही टूटी और उनमें गोबर फैला मिली। आश्रय केन्द्र की सफाई व्यवस्था चौपट मिली। केन्द्र में खरीदे गए चारे का स्टॉक रजिस्टर समेत सारे अभिलेख नदारद मिले। केन्द्र में बीमार गोवंश के लिए सिक वार्ड नहीं बनाए जाने पर भी एसडीएम ने फटकार लगाई। चारे के लिए किए गए भुगतान में खामियां पाकर भी एसडीएम बेहद खफा हुए। एसडीएम ब्रजेश कुमार वर्मा ने बताया निरीक्षण के समय मौजूद रहे बीडीओ और डिप्टी सीबीओ से रिपोर्ट मांगी गई है। जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गोवंश आश्रय केन्द्र की अव्यवस्थाएं दूर कराई जाएंगी।

एसपी बनकर मुकदमा निपटाने के लिए लाखों रुपए मांग रहा बर्खास्त सिपाही गिरफ्तार

● मोहनलालगंज पुलिस ने सीआरपीएफ के बर्खास्त हेड कांस्टेबल और उसकी परिचित युवती को भेजा जेल

संवाददाता। मोहनलालगंज

सीआरपीएफ का बर्खास्त हेड कांस्टेबल एसपी बनकर किसान के परिवार से छेड़छाड़ के मुकदमे में समझौता कराने के लिए लाखों रुपए मांग रहा था। जांच में इस बात का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी और छेड़छाड़ का केस दर्ज कराने वाली उसकी परिचित युवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को जांच में युवती द्वारा ही फोन करके आरोपी युवकों को होटल बुलाए जाने की बात भी साफ हो गई है। हालांकि युवती द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे की जांच अलग से की जा रही है।



नगरम के कमलापुर बिबलिका निवासी किसान छोटेलाल के बेटे दिलीप और अब्बास नगर निवासी गोल्डी के विरुद्ध निजी अस्पताल में कार्यरत युवती ने कुछ दिन पूर्व छेड़छाड़ का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई थी। उसी मुकदमे में सुलह समझौता कराने के लिए मूलरूप से झांसी निवासी कुलदीप उर्फ कमलापत यादव एडिशनल एसपी बनकर किसान

छोटेलाल को फोन कर 20 लाख रुपए मांग रहा था। काफी मिनतों के बाद भी कुलदीप ने 15 लाख रुपए से कम रकम न लेने की बात कही। यही नहीं जल्द रकम का इंतजाम न करने पर आरोपियों को जेल भिजवाने की धमकी दी। किसान छोटेलाल ने पुलिस अधिकारियों को रिफॉर्डिंग सुनाकर आपबीती बताई तो अधिकारी भी हैरत में पड़ गए। फौरन एफआईआर दर्ज कर आरोपी

तहसील के गेट पर जाम में फंसे एसडीएम, ट्रैफिक पुलिस रही बेखबर

संवाददाता। मोहनलालगंज

● मोहनलालगंज कस्बे में ट्रैफिक जाम की समस्या बन रही नासूर जिम्मेदार बेपरवाह

रहते हैं। गुरुवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ जब शाम करीब 4 बजे तहसील जा रहे एसडीएम ब्रजेश कुमार वर्मा की गाड़ी तहसील के गेट पर ही जाम में फंस गई। गेट पर गाड़ियां खड़ी होने से एसडीएम की गाड़ी अंदर नहीं जा सकी। लिहाजा एसडीएम गाड़ी से उतरकर पैदल ही तहसील चले गए।

इस दौरान जाम कोतवाली तक पहुंच गया लेकिन पुलिसकर्मियों बेपरवाह रहे। लिहाजा कुछ जागरूक वाहन चालकों ने खुद पहले की तब जाकर हाईवे पर वाहनों का आवागमन शुरू हो सका। इसी बीच हाईवे पर खड़ी गाड़ी हटती तब जाकर एसडीएम की गाड़ी भी तहसील के अंदर जा सकी।

पाकिंग के अभाव और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से मोहनलालगंज में जाम की समस्या नासूर बनती जा रही है। हाईवे पर वाहन पाकिंग की वजह से गुरुवार को एसडीएम को गाड़ी भी काफी देर तक तहसील गेट पर जाम में फंसी रही। थकहार कर एसडीएम लिखाने वाली युवती से परिचय है। कुलदीप ने ही रुपए पेट्टे के लिए साक्षात् रची और छेड़छाड़ के मुकदमे में आरोपियों के परिवार को एसपी बनकर फोन किया और समझौता कराने के लिए 15 लाख रुपए की मांग की। सीडीआर से साफ हुआ कि युवती ने ही आरोपी युवकों को फोन कर होटल बुलाया था फिर उसी ने कुलदीप को भी फोन किया। इस पूरे मामले में कुलदीप के साथ ही युवती की भी भूमिका पाई गई। इसलिए दोनों को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया है।

केजरीवाल की रणनीति

आतिशी मुख्यमंत्री

आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाना केजरीवाल की रणनीति का हिस्सा है जिससे वह महिला मतदाताओं को आकर्षित करना चाहते हैं। एक आश्चर्यजनक, पर रणनीतिक राजनीतिक कदम के रूप में उत्साही तथा शिक्षा सुधारवादी के रूप में सुपरिचित आतिशी दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गई हैं। यह परिवर्तन न केवल दिल्ली के राजनीतिक इतिहास, बल्कि भारतीय राजनीति के व्यापक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। आतिशी को जिम्मेदारी सौंपने के अरविंद केजरीवाल के निर्णय को सुनियोजित कदम बताया जा रहा है जिससे 'पीढ़ीगत परिवर्तन' तथा प्रशासन के प्रति नए दृष्टिकोण का संकेत मिलता है। आतिशी को केजरीवाल द्वारा पसंद करने के अनेक कारण हैं जिनमें से प्रत्येक के अपने राजनीतिक और प्रशासनिक तर्क हैं। आतिशी आम आदमी पार्टी-आप के गठन के समय से उसका सबसे चमकदार चेहरा रही हैं। उनको खासकर शिक्षा के क्षेत्र में अपने खोजी विचारों तथा प्रशासन से सीधे संबंधों के लिए जाना जाता है। शिक्षा मंत्री के रूप में उनके काम पर पूरे देश का ध्यान गया क्योंकि उनके नेतृत्व में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। केजरीवाल द्वारा उनको पदोन्नत करने का फैसला ऐसे समय आया है जब 'आप' अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। दिल्ली की बढ़ती शहरी ढांचागत संरचना के प्रबंधन के साथ केन्द्र सरकार के साथ नाजुक संबंधों में संतुलन की आवश्यकता को देखते हुए शहर को नई ऊर्जा तथा खोजी समाधानों की आवश्यकता है। अपनी प्रशासनिक क्षमता तथा सुधारवादी सार्वजनिक छवि के चलते आतिशी ऐसा व्यक्ति हैं जो दिल्ली को जटिल मुद्दों से बाहर निकाल सकती हैं। केजरीवाल के इस कदम से 'आप' नेतृत्व में युवा पीढ़ी को शामिल करने की इच्छा प्रकट होती है। आतिशी को पदोन्नति से वे न केवल दिल्ली का तात्कालिक भविष्य, बल्कि पार्टी का दीर्घकालीन दृष्टिकोण भी तैयार कर रहे हैं जिसमें भारतीय राजनीति में 'आप' को एक प्रगतिशील व युवा-केन्द्रित शक्ति के रूप में पेश किया जाएगा।

आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उम्मीदों की नई लहर पैदा हुई है। उनके रिकार्ड से स्पष्ट होता है कि शिक्षा और सार्वजनिक कल्याण उनकी प्रमुख प्राथमिकतायें होंगी। दिल्ली के निवासी उन पहलों के विस्तार की उम्मीद कर सकते हैं जो पहले ही लाभकारी रही हैं। इनमें 'मुहल्ला क्लीनिकें', जल एवं बिजली योजनायें तथा स्वास्थ्यरक्षा और शिक्षा पर ध्यान देना शामिल हैं। आतिशी के नेतृत्व का सर्वाधिक प्रमुख आयाम ऐसे प्रशासन का नया दृष्टिकोण पेश करने की क्षमता है जो कम टकराव वाला तथा ज्यादा सहयोगी हो। दिल्ली के सर्वोच्च पद तक आतिशी की पदोन्नति एक महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि असली शक्ति अरविंद केजरीवाल के पास बनी रहेगी। पार्टी के सभी प्रमुख निर्णय वही करेंगे, लेकिन आतिशी की पार्टी में पदोन्नति भी वास्तविक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे केवल कुछ महीनों तक मुख्यमंत्री रहेंगी क्योंकि दिल्ली में मतदान थोड़े ही दिन में होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद उनका कार्यकाल महिलाओं में चर्चा का विषय रहेगा। दिल्ली के साथ ही यह कार्यकाल पिछले दशक में हुए सुधारों की निरंतरता प्रदर्शित करेगा। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसमें शहर के भविष्य के लिए नए विचारों और नई ऊर्जा का भी समन्वय होगा। यह आतिशी की नेतृत्व गुणवत्ता की परीक्षा होगी क्योंकि उन पर लगातार समर्थक व विरोधी अपनी नजर बनाए रखेंगे। दबावों से बाहर निकलने की उनकी क्षमता पर केजरीवाल के इस साहसी निर्णय की सफलता निर्भर करेगी।



आतिशी

जल संकट से निपटने के उपाय

भारत की झीलों व दलदली क्षेत्र एक समय में शहरों की जीवनरेखा होते थे, पर आज वे खतरनाक गति से गायब हो रहे हैं। इसका कारण व्यापक भ्रष्टाचार तथा बेलगाम निर्माण है।



कोटा श्रीराज (लेखक, नीति विश्लेषक हैं)



भारत की झीलों व दलदली क्षेत्र एक समय में शहरों की जीवनरेखा होते थे, पर आज वे खतरनाक गति से गायब हो रहे हैं। इसका कारण व्यापक भ्रष्टाचार तथा बेलगाम निर्माण है। शहरी झीलों व दलदली क्षेत्र हमारी परिस्थितिकी का अभिन्न अंग हैं। वे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे पेयजल का स्रोत हैं, भूमिगत जल का पुनर्भरण करते हैं तथा आजीविका के साथ ही जैव-विविधता बनाए रखने में सहायक हैं। लेकिन देश की जनसंख्या में लगातार वृद्धि, भ्रष्ट प्रशासकों तथा निर्माण माफिया के कारण इन जल भंडारों का जीवन संकट में पड़ गया है। दुनिया भर में दलदली भूमियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था 'वेटलैंड्स इंटरनेशनल' द्वारा किए गए अध्ययन की अनुसार, पिछले 30 साल में भारत में हर पांच वेटलैंड में से दो नष्ट हो गए हैं और बाकी वेटलैंड जल भंडारों में क्षमता का केवल 40 प्रतिशत जल है जिससे वे जल की गुणवत्ता नष्ट होने के कारण जलीय जीवों के उपयुक्त नहीं रह गए हैं।

श्रीरंगपटना के बीच वैकल्पिक मार्ग बेंगलुरु के कारण संभव नहीं हुआ था जो झीलों और जल भंडारों से भरा था। इस खोज का नेतृत्व करने वाले कैप्टेन ने दलदली भूमियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था 'वेटलैंड्स इंटरनेशनल' द्वारा किए गए अध्ययन की अनुसार, पिछले 30 साल में भारत में हर पांच वेटलैंड में से दो नष्ट हो गए हैं और बाकी वेटलैंड जल भंडारों में क्षमता का केवल 40 प्रतिशत जल है जिससे वे जल की गुणवत्ता नष्ट होने के कारण जलीय जीवों के उपयुक्त नहीं रह गए हैं।

विडंबना है कि देश की आर्थिक प्रगति होने के साथ ही भारत में शहरों, ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में बेलगाम निर्माण तथा खेती और आवास के लिए जल भंडारों को लगातार नष्ट किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तालाब जनजीवन का अभिन्न अंग होने के साथ ही अनेक लोगों की आजीविका का साधन होते थे, पर अब वे लगभग विलुप्त हो रहे हैं। तालाबों के नष्ट होने के कारण अधिकांश गांवों में जल-चक्र असंतुलित हो गया है जिसका प्रभाव अनेक प्रकार से दिखाई देता है।

राज्य सरकार की 'हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असेट प्रोटेक्शन एजेंसी'-हाइड्रा ने हैदराबाद तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में कब्जा किए गए जल भंडारों को मुक्त करने का अभियान छेड़ा जो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में स्थान प्राप्त कर सका। इस वर्ष जुलाई में गठित हाइड्रा टीम की अध्यक्षता एक आईपीएस अधिकारी कर रहे हैं।

उनको राज्य के मुख्यमंत्री रेवत रेड्डी ने स्पष्ट आदेश किये हैं कि शहर के जल भंडारों को अवैध कब्जों और निर्माणों से मुक्त कराया जाए। हाइड्रा ने 'फुल टैक लेवल'-एफटीएल को मानक बनाया है। इसके अनुसार एफटीएल के आधार पर 30 मीटर के क्षेत्र में किसी निर्माण या कब्जे को गिरा दिया जाना है। इस हाइड्रा एजेंसी को कामकाज की पूरी स्वतंत्रता दी गई है और वह राजनीतिक दबावों से पूरी तरह मुक्त होकर पूर्ण असहियुता के साथ काम कर रही है। इसने शहर के प्रमुख राजनेताओं व बिजनेसमैनों के अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त किया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के भाई को भी विध्वंस करने की नोटिस दी गई थी। इस अभियान को पूरी दृढ़ता के साथ बिना किसी दबाव के चलाया गया और वह जल भंडारों, सरकारी जमीनों, शहरी नहरों तथा पार्कों से शहर के 23 स्थानों से 262 अवैध कब्जे हटाने में सफल रहा। इससे अब तक 112.72 एकड़ जमीन वापस प्राप्त की जा सकी है। राज्य सरकार ने यह आदेश

भी दिया है कि झीलों के निकट कोई निर्माण करने के पहले हाइड्रा से एनओसी लेना जरूरी हो गया है। हाइड्रा की कार्यवाही से न केवल तेलंगाना, बल्कि पूरे भारत में पर्यावरणविदों में विश्वास की भावना पैदा हुई है। इसे पर्यावरण संरक्षण तथा जल भंडारों की रक्षा के लिए खास प्रशासनिक अध्ययन की तरह देखा जा रहा है। लेकिन जैसा हर पहल के साथ होता है, हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा की जा रही इस असाधारण पहल की व्यापक आलोचना हो रही है। गरीबों तथा घरों के कर्ज की अदायगी करने वालों के घर नष्ट होने के कारण इसे अमानवीय बताया जा रहा है। इस स्थिति के कारण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पाएगा। निराशाजनक और सूखे भविष्य से बचने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों तथा स्थानीय पर्यावरण समूहों के साथ सहयोग कर हर राज्य में एक 'वेटलैंड टास्क फोर्स' का गठन करना चाहिए। राज्य-विशिष्ट टास्क फोर्स को

स्पष्ट आदेश मिलना चाहिए कि वह अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले हर जल भंडार को सारे कब्जे हटा कर बहाल करे, अवैध निर्माणों को ध्वस्त करे तथा भूमि प्रयोग में परिवर्तन को रोके। टास्क फोर्स को नियम लागू कराने के साथ ऐसी सक्षमकारी भूमिका भी अदा करनी चाहिए जिसका उद्देश्य अपने क्षेत्राधिकार की सभी दलदली भूमियों व जल भंडारों को भरना और पुनर्जीवित करना हो। उदाहरण के लिए, टास्क फोर्स शहरी परिवारों और बिजनेसों को अपने परिसरों में वर्षाजल संरक्षण व्यवहार अपनाने को प्रेरित कर सकती है। इस प्रकार संरक्षित जल भूमिगत जल का स्तर सुधारने तथा जल स्रोतों को समृद्ध करने का काम कर सकता है। इसके साथ ही सरकार टास्क फोर्स को शहरी क्षेत्रों में बोरवेल नियंत्रित करने को भी कह सकती है। महानगरीय क्षेत्रों में बेलगाम और अनियंत्रित ढंग से पानी निकालने के कारण भूमिगत जल सूख रहा है। टास्क फोर्स बोरवेल बनाने के पहले पूर्व अनुमति अनिवार्य बना कर भूमिगत जल भंडारों को सुरक्षित कर सकती है। इसके साथ ही टास्क फोर्स टीम यह सुनिश्चित करने के लिए पानी के मीटर लगा सकती है कि जल का प्रयोग और उसकी गुणवत्ता मापी जा सके। वर्तमान समय में इस बात के अनेक उदाहरण हैं कि राजनीतिक संपर्कों वाले स्थानीय नेता उनको संरक्षण करने के नाम पर झीलों और जल भंडारों को 'गोद लेते' हैं और धीरे-धीरे उन पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद बिल्डर माफिया से मिलीभगत कर निर्माण किया जाता है और इस संपत्ति को मासूम नागरिकों को बेच दिया जाता है। वेटलैंड टास्क फोर्स इस दुष्प्रक्र को रोक सकती है तथा यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि संरक्षण के नाम पर झीलों व जल भंडारों का प्रबंधन करने वाला कोई व्यक्ति या वार्पियनिक कंपनी इसका दुरुपयोग न कर सके। जल भंडार भारत की जीवनरेखा हैं। इसे देखते हुए समाप्त हो गए जल भंडारों और झीलों को पुनर्जीवित करना तथा बचे हुए भंडारों और झीलों की सुरक्षा करना देश के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। केवल ऐसी कठोर, निष्पक्ष तथा त्वरित कार्यवाही से ही देश का भविष्य सुनिश्चित हो सकता है कि उसे जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

भारत की अप्रयुक्त समुद्री ऊर्जा क्षमता

भारत की आठ हजार किलोमीटर लंबी तटरेखा में प्रतिवर्ष 9.2 लाख ट्रिलियन वाट घंटा स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है।



कुमार चेलपान (लेखक दिपायनियर के विशेष संपादक हैं)

8000 किलोमीटर लंबी भारतीय तटरेखा में प्रतिवर्ष 9.2 लाख ट्रिलियन वाट घंटा बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है, जो आज की तारीख में उत्पादित बिजली से कई गुना अधिक है। यह ऐसे समय में है जब भारत ऊर्जा उत्पादन के सभी स्रोतों का उपयोग करके 4.5 लाख मेगावाट बिजली की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है।



डेनमार्क, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों ने इस क्षेत्र में विशाल प्रगति की है। डेनमार्क का कहना है कि लवणता ढाल का दोहन करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा बिजली स्टेसन स्थापित करने की व्यापक गुंजाइश है। आईएनसीओआईएस के निदेशक डॉ. टी. श्रीनिवास कुमार ने कहा कि एटलस ऊर्जा जी-20 देश सामूहिक रूप से कुल नवीकरणीय ऊर्जा का 81 प्रतिशत और लगभग 100 प्रतिशत महासागर ऊर्जा के लिए जिम्मेदार हैं। भारत की अपतटीय पवन ऊर्जा का दोहन नहीं हुआ है, जबकि

के निर्वहन के बारे में किसी भी तरह की आशंका नहीं होगी। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने कहा, यह ऊर्जा का सबसे स्वच्छ रूप है और कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्यमों ने अक्षय ऊर्जा इकाइयों स्थापित करने में अपनी रुचि दिखाई है। आईएनसीओआईएस मछुआरों को संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्रों और मौसम के सटीक पूर्वानुमानों के बारे में जानकारी प्रदान करके देश के ब्लू इकोनॉमी क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभा

रहा है। डॉ. श्रीनिवास कुमार और उनकी टीम ने एक अत्याधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली विकसित की है, जिसके साथ वे हिंद महासागर के किनारे के देशों को सचेत करते हैं। 1999 में अपनी स्थापना के बाद से, इनकाइस अपने प्रमुख कार्यक्रमों जैसे संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र, महासागर की स्थिति का पूर्वानुमान और सुनामी प्रारंभिक चेतावनी सेवाओं के माध्यम से भारत की नौली अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। इनकाइस इन-सीटू-सिम्युलेटेड उत्पादों में फेले समुद्र विज्ञान संबंधी डेटा का राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भंडार भी रहा है।

आप की बात

सिंधु संधि की समीक्षा

भारत ने 6 दशक पुरानी सिंधु जल संधि की समीक्षा को बेहद जरूरी बताया है। इससे पहले पाकिस्तान को अपनी बात से नोटिस भेजा है। किशनगंगा और रातेले जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में अरसे से चल रहे विवाद के मद्देनजर अब यह नोटिस पाकिस्तान को भेजा गया है। भारत का तर्क है कि परिस्थितियों में मौलिक और अत्युत्पासित परिवर्तनों के कारण समझौते की समीक्षा करना बेहद जरूरी है। भारत ने प्रमुख तौर पर तीन चिंताएं व्यक्त की हैं जिसमें जनसंख्या में परिवर्तन, पर्यावरणीय मुद्दे एवं भारत के उत्सर्जन प्रदेशों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी की जरूरत शामिल है। सीमापार से लगातार जारी आतंकवाद के प्रभाव को भी समीक्षा का कारण बताया गया है इन सब मुद्दों पर भारत में दोनों देशों के बीच जल्द आधिकारिक बातचीत शुरू करने की जरूरत बताई गई है। विडंबना है कि भारतवर्ष आजादी के बाद से ही अपने देश में समुचित ढांचागत संरचना बनाने में सफल नहीं होने के कारण सिंधु जल का अपने हिस्से का पानी भी पाकिस्तान में जाने देता था। मोदी सरकार ने अब नहरों का व्यापक निर्माण कर यह कमी पूरी कर दी है। इससे भारत सिंधु से अपने हिस्से का पानी लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए समीक्षा की बात कर रहा है।

मायावती का दृष्टिकोण

बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती अपनी राजनीति में आमतौर से देश को प्रथम स्थान पर रखती दिखाई देती हैं। भारत का विपक्ष सरकार के हर निर्णय का विरोध ही करता आया है, चाहे वह निर्णय देशहित में ही क्यों न हो। परन्तु राजनीतिक संकट का सामना करते हुए भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी इस राजनीति में बदलाव नहीं किया और हमेशा तटस्थ व न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाया। भारत सरकार लिए देशहित के निर्णयों का मायावती ने समर्थन किया है। हाल ही में भारत सरकार ने एक देश एक चुनाव के बिल को केबिनेट में मंजूरी दी तो पूरा विपक्ष उसके विरोध में आ गया, लेकिन मायावती ने खुलकर इस बिल का समर्थन करते हुए कहा है कि यह कदम देश के हित में है। सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक व एयर स्ट्राइक का सुश्री मायावती ने समर्थन किया था। सुश्री मायावती ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का खुला समर्थन किया था क्योंकि इसके कारण वहां एससी एसटी को आरक्षण समेत अनेक सुविधाओं से वंचित रखा गया था। देश हित के मामलों पर दलगत राजनीति को दूर रखने वाली सुश्री मायावती से विपक्ष की सीखना चाहिए। इस प्रकार मायावती ने स्वयं को बाबा साहेब अंबेडकर की ईमानदार अनुयायी सिद्ध किया है।

हाँकी टीम की विजय

भारतीय हॉकी टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए एशिया चैंपियन हॉकी खिताब के लिए फ़इनल में चीन को हराकर भारत को एशिया हॉकी का सिरमौर बना दिया है। इस शानदार उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय हॉकी टीम एक टीम के कप्तान सरपंच हरमनप्रीत सिंह ने सभी भारतवासियों का दिल जीत लिया है। इस शानदार उपलब्धि के पीछे खिलाड़ियों की एकजुटता और उल्टू खेल का प्रदर्शन है जिसने पांचवीं बार भारत को यह खिताब दिलाया है। यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दिग्गज भारतीय गोलकीपर श्रीजेश के बिना जीत दर्ज की है। भारत इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी

अफगान महिलायें

महिलाओं को नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए तालिबान पर दबाव डाला जाना जरूरी है। मगर तुनिया के अधिकांश देश अपने फयदे के सौदे तालिबान के साथ कर रहे हैं। तालिबान ने सरकार बनाने के बाद महिलाओं और लड़कियों को इस्लामी कानून-कानूनों के अंतर्गत अधिकार देने का वादा किया था, लेकिन आज किसी भी अन्य इस्लामी देश की तुलना में अफगान महिलायें और लड़कियां गुलामी की शिकार हैं। विडंबना है कि इस पर इस्लामी देश तथा इंग्लैंड जैसे संस्थाएं दूर खड़े होकर तमाशा देख रही हैं। अफगान

भारतीय रक्षा उद्योग को अफ्रीका में साझेदारी की उम्मीद

जोहानिसबर्ग। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की आठ और निजी क्षेत्र की दो रक्षा उपकरण विनिर्माता कंपनियां अफ्रीका एयरोस्पेस एंड डिफेंस एक्सपो में हिस्सा ले रही हैं। ये कंपनियां अपने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को प्रदर्शित कर रही हैं और बिज्नी के बाद उनके रखरखाव में सहयोग की पेशकश कर रही हैं। अफ्रीका एयरोस्पेस एंड डिफेंस (एएडी) में हिस्सा ले रहे अधिकारियों ने बताया कि रखरखाव को एक महत्वपूर्ण बरक मानते हुए रक्षा क्षेत्र की इन शीर्ष कंपनियों को विश्वास है कि वायु, भूमि और समुद्री उत्पादों में भारत की क्षमता को महाद्वीप और वैश्विक स्तर पर परमंद किया जाएगा।

दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी च्चैन में स्थित वाय्स्कूप्फ वायुसेना केंद्र पर आयोजित एएडी प्रदर्शनी देश के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान देने वाले आयोजनों

में से एक है। इस साल 18 से 22 सितंबर तक एएडी के तहत प्रदर्शनी और एयर शो आयोजित किया जा रहा है।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उच्चायुक्त प्रभात कुमार ने प्रदर्शनी में भारत के पेंवेलियन क्रा बुधवार को आधिकारिक उद्घाटन करने के बाद कहा, हमारे उत्पादों ने लड़ाई की स्थिति में अच्छा प्रदर्शन किया है और इसलिए वे अफ्रीकी देशों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। मुझे भरोसा है कि वे इन उत्पादों को खरीद करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के उद्यम आमर्ड व्हेकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजय द्विवेदी ने कहा कि यह पहली बार है कि वे प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं।

एवीएनएल 1962 से ही अलग-अलग प्रकार के टैंक, लड़ाकू वाहनों और बास्की सुगं से बचने में सक्षम वाहनों

और टैंक के इंजन का उत्पादन कर रहा है। द्विवेदी ने कहा, हम जानते हैं कि अफ्रीका के रक्षा बाजार में बहुत अधिक संभावना है और हम अपने उत्पाद को बेच सकते हैं और साथ ही उनके वाहनों के बनाने और आधुनिकीकरण में मदद कर सकते हैं। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के विपणन महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि कंपनी अपने नवीनतम उत्पाद आधुनिक हल्केहेलीकॉप्टर को प्रदर्शित कर रही है। भारत उद्यमनामस लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक गिरीश प्रधान ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को आपूर्ति किए जा रहे लड़ाकू हथियारों की दक्षिण अफ्रीका में तेजाती की क्षमर्षे संभावनाएं हैं। इसके अलावा अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और व्यावसायिक अवसरों की तलाश करते वाली कंपनियों में इंडिया ऑल्टै, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड शामिल हैं।

सांप्रदायिक हिंसा की दो हजार से अधिक घटनाओ मे नौ लोगों की मौत

ढाका। हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के एक अल्पसंख्यक समूह ने बुरस्पतिवार को कहा कि चार से 20 आगस्त के बीच सांप्रदायिक हिंसा की दो हजार से अधिक घटनाओं में कम से कम नौ लोग मारे गए और 69 उपानसा स्थलों पर हमला किया गया तथा तोड़फोड़ की गई। डेली स्टार समाचार पत्र की खबर के अनुसार बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई ओडिया परिषद के नेता निर्मल रोजारियो ने संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में सांप्रदायिक हिंसा की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का आह्वान किया। संघटन के उपाध्यक्षों में से एक निर्मल रोजारियो के हवाले से अखबार ने खबर में बताया कि चार से 20 आगस्त के बीच देशभर के 76 जिलों और महानगरीय क्षेत्रों में से 68 में सांप्रदायिक हिंसा की कुल 2,010 घटनाएं हुईं, जिसके परिणामस्वरूप नौ लोगों की मौत हो गई।

सांप्रदायिक हिंसा का ब्योरा देते

कनाडा ने अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए अध्ययन परमिट मे कटौती की

ओटावा। कनाडा ने अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए अध्ययन परमिट में कटौती करने का ऐलान किया है जिससे बहुत से भारतीय नागरिकों के प्रभावित होने की आशंका है। प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने बुधवार देर रात एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हम इस साल 35 फीसदी कम अंतरराष्ट्रीय छात्र परमिट जारी कर रहे हैं तथा आगले साल इसमें 10 फीसदी और कमी की जाएगी। आत्रजन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है, लेकिन जब खराब तत्व व्यवस्था का दुसुपरण करते हैं और छात्रों का फायदा उठाते हैं, तो हम कार्वाई करते हैं। यह कदम तब उठाया गया है जब कनाडा सरकार अस्थाई निवासियों की संख्या कम करने पर विचार कर रही है। कनाडा भारतीय विद्यार्थियों के लिए सबसे पर्सदीदा गंतव्यों में से एक है। टूडो की घोषणा से कनाडा में पढ़ने की इच्छा रखने वाले कई भारतीय छात्रों पर असर पड़ने की संभावना है।

ट्रंप के अभियान से चुराई जानकारी को बाइडन के अभियान से जोड़ने की नाकाम कोशिश हुई

वाशिंगटन। ईरानी हैकरों ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के अभियान को उनके प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप के अभियान से चुराई गई जानकारी से जोड़ने की कोशिश की और 2024 के चुनाव में हस्तक्षेप करने के प्रयास के तहत उन्होंने राष्ट्रपति से जुड़े लोगों की अनचाहे ईमेल भी भेजे। अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) और अन्य संघीय एजेंसियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि मेल पाने वाले किसी भी व्यक्ति ने जवाब दिया, जिससे हैक की गई जानकारी को चुनाव के अंतिम महीनों में फेलने से रोका जा सका।

हैकरों ने जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में बाइडन के अभियान से जुड़े लोगों को ईमेल भेजे थे, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद बाइडन ने राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया। ईमेल में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के अभियान से चुराई गई, गैर-सार्वजनिक सामग्री से लिया गया एक

अंश शामिल था। इससे पहले भी एफबीआई और अन्य संघीय एजेंसियां ईरान पर हैक और लीक का सहारा लेकर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा चुकी हैं। एफबीआई, राष्ट्रीय खुफिया एवं साइबर सुरक्षा तथा अवसंरचना सुरक्षा एजेंसी कार्यालय ने कहा है कि ट्रंप के अभियान की जानकारी हैक करना और बाइडन-हैरिस के अभियान में संध लगाने का प्रयास चुनाव में मतदाताओं के विश्वास को कम करने तथा विवाद भड़काने के प्रयास का हिस्सा है। ट्रंप ने जवाब दिया, जिससे हैक की गई जानकारी को चुनाव की जानकारी को हैक कर लिया गया है। उसने कहा कि ईरानी हैकरों ने संवेदनशील गुप्त दस्तावेज चुरा लिए हैं तथा उन्हें वितरित किया है। कम से कम तीन समाचार संस्थानों – पोलिटिको, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वाशिंगटन पोस्ट को ट्रंप अभियान की अंदरूनी गोपनीय सामग्री लीक की गई थी।

पाक ने भारत से सिंधु जल संधि के प्रावधानों का सम्मान करने का आग्रह किया

इस्लामाबाद। भारत द्वारा सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस दिए जाने के कुछ दिनों बाद, इस्लामाबाद ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह इस समझौते को महत्वपूर्ण मानता है और उम्मीद करता है कि नई दिल्ली भी इसके प्रावधानों का पालन करेगा। भारत और पाकिस्तान ने नौ वर्षों की वार्ता के बाद 19 सितंबर 19६0 को सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका एकमात्र उद्देश्य सीमा पार की नदियों का प्रबंधन करना था। नई दिल्ली में बुधवार को सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारत ने 30 आगस्त को पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस भेजकर 64 साल पुराने समझौते की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें उसने परिस्थितियों में मौलिक और अप्रत्याशित बदलावों और सीमा पार से लगातार जारी आतंकवाद के प्रभाव का हवाला दिया था। भारत के नोटिस पर एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहा बलूच ने यहां संवाददाताओं से कहा, पाकिस्तान सिंधु जल संधि को महत्वपूर्ण मानता है और उम्मीद करता है कि भारत भी इसके प्रावधानों का पालन करेगा। बलूच ने बताया कि दोनों देशों के बीच सिंधु जल आयुक्तों का एक तंत्र है और संधि से जुड़े सभी मुद्दों पर इसमें चर्चा की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि संधि से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए कोई भी कदम समझौते के प्रावधानों के तहत ही उठाया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि विदेश कार्यालय के प्रवक्ता की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि पाकिस्तान उस समझौते में संशोधन में रुचि नहीं रखता है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच जल बंटवारे के जटिल मुद्दे का समाधान किया गया था। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख समझौतों में से एक है, जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है और दोनों पड़ोसियों के बीच युद्धों और तनावों के बावजूद इसका पालन किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन के प्रस्ताव पर मतदान से भारत अनुपस्थित रहा

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में उस प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें इजराइल से एक साल के भीतर कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में उसकी अवैध उपस्थिति समाप्त करने की मांग की गई। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि वह बातचीत और कूटनीति का प्रबल समर्थक है और विभाजन को बढ़ाने के बजाय सेतु बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस संबंध में 193 सदस्य्य महासभा ने बुधवार को प्रस्ताव को पारित कर दिया, जिसके पक्ष में 124 देशों ने, विरोध में 14 देशों ने मतदान किया और भारत समेत 43 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

यूएनजीए में पूर्वी यरशलम सहित कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में इजराइल की निरंतर अवैध मौजूदगी से

उत्पन्न कानूनी परिणामों पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की राय शीर्षक से प्रस्ताव पारित किया गया। जिन देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, उनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, नेपाल, यूक्रेन और ब्रिटेन शामिल हैं। इजराइल और अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।

प्रस्ताव पर मतदान के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि, राजदूत परवर्तेनी हरीश ने इजराइल-फलस्तीन मुद्दे का न्यायसंगत, शांतिपूर्ण और स्थाई समाधान प्राप्त करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और दोहराया कि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष और सार्थक वार्ता के माध्यम से दो-राष्ट्र समाधान से ही स्थाई शांति प्राप्त होगी। उन्होंने कहा, भारत आज के मतदान से दूर रहा। हमलोग बातचीत और लोकतंत्र के दृढ़ समर्थक रहे हैं। हमारा मानना है कि

संघर्ष के समाधान का कोई और रास्ता नहीं है।

हरीश ने जोर दिया कि युद्ध में कोई विजई नहीं होता। उन्होंने कहा कि संघर्ष में सिर्फ लोगों की जान जाती है और तबाही होती है। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों को करीब लाने की दिशा में संयुक्त प्रयास होना चाहिए, न कि उन्हें और दूर करने की दिशा में। हमें सेतु बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए, न कि विभाजन को और बढ़ाना चाहिए। भारत ने महासभा से शांति के लिए वास्तविक प्रयास करने का आग्रह किया। हरीश ने संघर्ष के समाधान और मानवीय पीड़ा को समाप्त करके शांति की बहाली के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हम इसी भावना से प्रेरित होते रहेंगे। हम स्थाई शांति प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए तैयार हैं।

वर्ल्ड बेस्ट स्कूल पुरस्कार के लिए दिल्ली और रतलाम के विद्यालयो ने अतिम दौर मे बनाई जगह

लंदन। वर्ष 2024 के वर्ल्ड बेस्ट स्कूल पुरस्कार के फाइनल में बृहस्पतिवार को जगह बनाने वाले विद्यालयों में दिल्ली और मध्य प्रदेश के दो नवोन्मेषी विद्यालय शामिल हैं। पुरस्कार जीतने के लिए ए दोनों स्कूल अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों से मुकाबला करेंगे। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित रयान इंटरनेशनल स्कूल और मध्यप्रदेश के रतलाम स्थित सीएम आरआईएसई स्कूल ने फाइनल में जगह बनाई है। यह पुरस्कार एक्सेंसर, अमेरिकन एक्सप्रेस और लेमन फाउंडेशन के सहयोग से लंदन स्थित टी4 एजुकेशन द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें विजेताओं के साथ 50,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि साझा की जाती है। रयान इंटरनेशनल स्कूल माध्यमिक विद्यालय तक है जो हाइड्रोपोनिक्स और बायोगैस संयंत्रों जैसी नवीन परियोजनाओं के माध्यम से पानी की कमी और दूषण से निपटने के लिए पर्यावरणीय कार्यों के लिए वर्ल्ड बेस्ट स्कूल पुरस्कार जीतने की दौड़ में शामिल है।



डोनाल्ड ट्रंप व डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस चुनाव प्रचार करते हुए।

भारत 2014 में 10वे स्थान से आगे बढ़कर 2019 में 5वी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना: पुरी

ह्यूस्टन (अमेरिका)। पेट्रोलियम मंत्री हरीदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की और कहा कि देश 2014 में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था जबकि 2019 में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए वह पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूत डी.सी. मंजूनाथ द्वारा यहां इंडिया हाउस में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में पुरी ने वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र, खासकर हरित हाइड्रोजन और एयरोस्पेस (वांतरिक्ष) में ह्यूस्टन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने अमेरिका-भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग की आधारशिला बताया।

पुरी ने हाल के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दल की रणनीतिक सफलताओं को रेखांकित किया और कहा कि मोदी के शासन में 2014 में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर देश 2019

तक ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मंत्री ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी शहरी विकास पहलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि देश ने 2017 से 2024 तक शहरी योजनाओं के लिए 25 अरब अमेरिकी डॉलर (1.57 लाख करोड़ रूपए) खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है।

पुरी ने ऊर्जा नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में ह्यूस्टन की सराहना की और कहा कि 2019 में हाइडी मोदी जैसे कर्तव्यक्रमों ने भारतीय-अमेरिकी संबंधों को ताकत को दर्शाया है। मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों, खासकर चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग में भारतीय प्रवासियों के योगदान की सराहना की तथा विदेश में रहते हुए भी सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने ह्यूस्टन में गर्मजोशी के आतिथ्य स्वत्कार के लिए भारतीय समुदाय का आभार व्यक्त किया और भारत की वैश्विक छवि को बढ़ाने में उनकी भूमिका की सराहना की।

द कन्वर्सेशन। पर्थ

ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाए का लेकर जारी बहस के बीच मेटा ने इंस्टग्राम पर किशोरों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है। इसके तहत मेटा ने इंस्टग्राम पर नए किशोर खातों का एक विकल्प दिया है। इन निजी खातों में विषयवस्तु और संदेशों को लेकर अधिकतम पाबंदियां होंगी, रात में नोटिफिकेशन रोकने का विकल्प होगा और किशोरों के लिए अपनी पसंद की सामग्री देखने के लिए नए तरीके शामिल होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इन खातों की निर्धारित सेंटिंस से बदलने के लिए एक माता-पिता की अनुमति की आवश्यकता होगी। इस कदम को माता-पिता के मन को शांति देने वाला बताया जा रहा है।

किशोर खाते (टीन अकाउंट्स) नई सुविधाओं और कई टूल का एक संयोजन है, जो पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन उन्हें वह स्वीकृति नहीं मिली है जो मेटा को चाहिए थी। इन परिवर्तनों को किशोर खातों के अंतर्गत लाने से ए परिवर्तन किशोरों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए अधिक दृश्यमान हो जाएंगे।

इन खातों वी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है:

- 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खाते निजी रहेंगे, लेकिन इनमें डिफॉल्ट सेंटिंग होगी। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे केवल माता-पिता की अनुमति से ही उस सेंटिंग को बदल सकेंगे।
- किशोर केवल उन्हीं लोगों से संदेश प्राप्त कर सकेंगे जिन्हें वे पहले से फॉलो कर रहे हैं या जिनसे वे जुड़े हुए हैं।
- विषयवस्तु से संबंधित पाबंदियां लगाने और कमेंट व मैसेज में आपत्तिजनक शब्दों को ब्लॉक करने के लिए सेंसर की जा सकेगी।
- रात 10 बजे से सुबह 7 बजे के बीच इंस्टग्राम पर नोटिफिकेशन आने बंद हो जाएंगे।

आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के नेतृत्व में ही अफ्रीकी संघ को जी-20 में शामिल कर इसका विस्तार किया गया था।

यही भविष्य है। कोविड-19 महामारी के दौरान वैकसीन कूटनीति के लिए भारत का दृष्टिकोण – यही भविष्य का रास्ता है। भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष में आप भागीदार को यह तय करने देते हैं कि हम आपके द्वारा प्रदान की गई धनराशि का उपयोग कैसे करें। यही आपसी सम्मान और एकजुटता का रास्ता है। किंग ने कहा, यह ग्लोबल साउथ में भारत के नजरिए से बहुपक्षवाद का नया रास्ता है। मैं भारत के बहुपक्षवाद के तरीके से बहुत प्रभावित हूं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व स्थाई प्रतिनिधि राजदूत रॉचर कंबोज ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को बहुपक्षवाद के लिए एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा जा रहा है।

